कैंपस प्लेसमेंट में धांधली: नैतिकता और छात्र हितों का हनन

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 29 | मूल्य 15 रुपये | 07-13 दिसंबर, 2025

फ्लाइट सिस्टम "बेपटरी" हवाई अड्डों पर कतारें

वर्ष 15 | अंक 29

दिव्य हिमगिरि

07-13 दिसंबर, 2025

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

दुनिया में कमजोर होता रूपया

पिछले कई दिनों से घरेलू शेयर बाजार में अनिश्चितता, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर असमंजस के बीच भारतीय मुद्रा भी कमजोर हो रही है। रुपया बुधवार को पच्चीस पैसे टूट कर 90.21 प्रति डालर के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। पिछले पांच दिनों से यह गिरावट देखी जा रही है। सवाल है कि डालर के मुकाबले भारतीय मुद्रा का मूल्य क्यों गिरता जा रहा है? यह निराशाजनक है कि दुनिया के प्रमुख देशों की मुद्रा की तुलना में रुपया कमजोर होता चला गया है। इसकी बड़ी वजह डालर की बढ़ती मांग के साथ विदेशी निवेशकों की शेयर बाजार से मुनाफावसूली भी मानी जा रही है। इसके अलावा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत पर अमेरिकी शुल्क लगाने का भी रुपए पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मगर सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक रुपए को संभालने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम क्यों नहीं उठा पा रहा है? इसमें कोई दोराय नहीं है कि अमेरिकी शुल्क की घोषणा के बाद से विदेशी निवेश का प्रवाह कम हुआ है और इसका असर घरेलू शेयर बाजार पर भी पड़ा है। मगर ऐसा लगता है कि सरकार इस स्थिति को शायद गंभीरता से नहीं ले रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का मानना है कि भारतीय मुद्रा में गिरावट चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इसका महंगाई या निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। उन्होंने अगले वर्ष की शुरूआत में डालर के मुकाबले रुपए में सुधार की उम्मीद जताई है। मगर अभी जिस हिसाब से भारतीय मुद्रा में गिरावट का सिलसिला जारी है, उसमें कितना और कैसे सुधार होगा, फिलहाल इसकी कोई साफ तस्वीर नजर नहीं आ रही है। अमेरिकी व्यापार समझौते और जीडीपी ग्रोथ से रुपये को सहारा मिल सकता है, जबकि आरबीआई की दर कटौती से उपभोग बढ़ेगा। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऊंचे टैरिफ की वजह से व्यापार किए जाने वाले निर्यात में कमी आ रही है। इसकी भरपाई करने के लिए भारत नए बाजार तलाश रहा है, जिसमें उसे कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। फिर भी रुपये में स्थिरता या मजबूती के लिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौता जरूरी है। रुपये में कमजोरी बुरी खबर इसलिए है क्योंकि भारतीय बाजार से विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। रुपये में कमजोरी से उनका मुनाफा घटता है क्योंकि वे इसे डॉलर में बदलते हैं। रुपये में गिरावट होने पर उसकी एवज में उन्हें कम डॉलर मिलते हैं। इसलिए भारतीय मुद्रा में कमजोरी से यह सिलसिला और तेज हो सकता है। आम तौर पर रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में रुपये को एक स्तर के आसपास बनाए रखने के लिए दखल देता है। इधर भी उसने ऐसा किया, लेकिन अभी विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है। इसलिए वह मुद्रा को स्थिर बनाए रखने के लिए बहुत दखल नहीं दे सकता। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी बैठक शुरू हुई है, जिसमें दरों में कटौती की संभावना है। हालांकि, इससे भारतीय मुद्रा पर दबाव बनने की आशंका है। मगर यह भी सही है कि दरों में कटौती से उपभोग को और बढ़ावा मिलेगा। उन्हें कौन दूर करेगा? जाहिर है कि इस सूरत में रिजर्व बैंक को रुपए के समर्थन में मजबूती से हस्तक्षेप करना होगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने के बाद भी रुपए में गिरावट थमेगी या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है। रुपया और कमजोर न हो, इसके लिए अब सभी स्तरों पर कदम उठाने की जरूरत है।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

फ्लाइट सिस्टम "बेपटरी" हवाई अड्डों पर कतारें

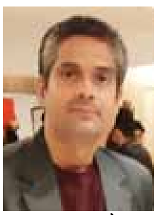
शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

इंडिगो की लगातार रद हो रही उड़ानों ने देशभर के एयरपोर्टों पर ऐसा तनाव और अव्यवस्था पैदा कर दी है, जिसकी कल्पना अक्सर सिर्फ फिल्मों में की जाती है। आमतौर पर सुचारू और समयबद्ध व्यवस्था के लिए पहचाने जाने वाले भारतीय हवाई अड्डों पर इन दिनों अफरातफरी, थकान और लंबी प्रतीक्षा यात्रियों की दिनचर्या बन गई है। एक-एक होकर उड़ानें कैंसिल होने लगीं तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में रातभर यात्रियों की कतारें बढ़ती चली गईं। बच्चे थककर फर्श पर लेट गए, बुजुर्ग व्हीलचेयर पर इंतजार करते-करते परेशान हो उठे, और कामकाजी लोगों के जरूरी शेडयूल बिखरते चले गए। शनिवार, 6 दिसंबर पांचवें दिन भी इंडिगो का बेपटरी फ्लाइट सिस्टम सुधरने की बजाय और चरमरा गया। चार दिनों में 2,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और रोजाना 500 से अधिक फ्लाइटें लेट हो रही हैं। ऐसा परिदृश्य भारतीय विमानन इतिहास में कम ही देखने को मिलता है, जहां यात्रियों के चेहरे पर थकान के साथ असहायता साफ झलकती हो। एयरपोर्ट स्टाफ भी भीड़ संभालने में बार-बार बैकफुट पर दिखा और घोषणाओं के बीच हर कोई अपनी उड़ान की संभावनाओं को लेकर दुविधा में फंसा रहा। बढ़ती अव्यवस्था के बीच केंद्र सरकार को अब सख्त हस्तक्षेप करना पड़ा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक हर हाल में क्लियर किए जाएं और किसी भी यात्री से रीशेडयूलिंग चार्ज न लिया जाए। देशभर के एयरपोर्टों पर यात्रियों की यह तकलीफ सिर्फ सिस्टम फेल की कहानी नहीं है। यह उन हजारों परिवारों, मरीजों, छात्रों, नौकरीपेशाओं और यात्रियों की गहरी बेबसी का चेहरा है, जो हर घंटे इस उम्मीद में खड़े रहे कि शायद अगली घोषणा उनके नाम की हो।

इंडिगो की लगातार रद होती उड़ानों ने देशभर के एयरपोर्टों पर यात्रियों की चिंता, थकान और असहायता की तस्वीर उजागर कर दी है। आमतौर पर सुव्यवस्थित और समय पर उड़ानों के लिए जाने जाने वाले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे हवाई अड्डों पर इस हफ्ते अब तक का सबसे लंबा इंतजार और अनिश्चितता का माहौल देखने को मिला। यात्रियों की लंबी कतारें रातभर एयरपोर्ट पर खिंचती रहीं, बच्चे थककर फर्श पर लेट गए, बुजुर्गों ने व्हीलचेयर पर घंटों बैठकर सहारा ढूंढा, और ऑफिस जाने वाले या मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए यात्रा करने वाले लोगों की पूरी योजना बिखर गई। चार दिनों में 2,000 से ज्यादा उड़ानों के रद होने और रोजाना 500 से अधिक उड़ानों में देरी ने यात्रियों की परेशानियों को चरम पर पहुंचा दिया। यह स्थिति न केवल इंडिगो के ऑपरेशन की कमी को उजागर करती है, बल्कि उन लाखों लोगों की बेबसी का भी चेहरा दिखाती है, जो अपने जरूरी

कामों और परिवार के लिए हर मिनट यह उम्मीद करते रहे कि शायद अगली घोषणा उनके नाम की होगी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार पांचवें दिन शनिवार को भी कोई सुधार नहीं दिखा। देश के चार प्रमुख एयरपोर्टों और कई बड़े शहरों से शनिवार को 400 से अधिक उड़ानें कैंसिल की गई। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। कहीं लोग अपने सामान के साथ फर्श पर बैठे हुए नजर आए, तो कहीं बच्चों को गोद में लेकर माता-पिता अपनी उड़ानों के बारे में लगातार पूछताछ कर रहे थे। यात्रियों की नाराजगी और थकान साफ नजर आ रही थी, जबकि एयरलाइन स्टाफ भी लगातार पूछताछ और शिकायतों का सामना करते हुए तनाव में दिखाई दिए। इस बढ़ती अव्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने तत्काल कदम उठाया। सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया कि वह बिना किसी देरी के सभी लंबित पैसेंजर रिफंड को पूरा करे। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन यात्रियों के ट्रैवल प्लान फ्लाइट कैंसिल होने के कारण प्रभावित हुए हैं, उनके लिए कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि रिफंड में किसी भी प्रकार की देरी और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब इंडिगो का ऑपरेशन लोगों के लिए परेशानी का कारण बना है, लेकिन लगातार पांचवें दिन भी उड़ानों का सिस्टम सुधार न होना और हजारों यात्रियों की योजनाओं के बाधित होने की स्थिति ने इसे और गंभीर बना दिया है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई के एयरपोर्ट पर रातभर यात्रियों की भीड़ देखी गई। लोग अपने बैग और जरूरी सामान के साथ इंतजार करते रहे, कहीं-कहीं तो लंबी कतारों के बीच धक्का-मुक्की भी नजर आई। यात्रियों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लगातार अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिससे इंडिगो और केंद्र सरकार दोनों पर दबाव बढ़ा। इस पूरे संकट के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बयान दिया कि नए पूर्ण ड्यूटी समय सीमा नियम 1 नवंबर से लागू हो चुके हैं, और इनमें किसी अन्य एयरलाइन को कोई परेशानी नहीं हुई है। इससे साफ है कि यह ऑपरेशन फेलियर केवल इंडिगो का है। उन्होंने यह भी कहा कि एयरलाइन की लापरवाही की पूरी जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई तय की जाएगी। सरकार ने पहले ही हवाई किराए पर लिमिट लागू की थी और कहा था कि अन्य एयरलाइंस को इसका कड़ाई से पालन करना होगा। यह लिमिट तब तक लागू रहेगी जब तक कि इंडिगो और पूरे एयरलाइन सिस्टम में स्थिरता नहीं आ जाती। पिछले चार दिनों में 2,000 से अधिक उड़ानों के रद्द होने के बाद, यात्रियों की नाराजगी चरम पर पहुंच गई। रोजाना औसतन 500 फ्लाइटें लेट हो रही हैं। यात्रियों ने बताया कि कई बार उन्हें अपने फिक्स्ड ट्रैवल प्लान के कारण मजबूरन इंतजार करना पड़ रहा है। कई छात्रों और नौकरीपेशाओं को इस स्थिति का सीधा असर पड़ा। कुछ लोगों ने एयरपोर्ट पर ही रात गुजारी, जबकि कुछ ने लंबी-लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर अपनी फ्लाइट की जानकारी पाई। यह सिर्फ ऑपरेशनल समस्या नहीं, बल्कि हजारों यात्रियों की जिंदगी में पैदा हुई असुविधा का भी संकेत है।

केंद्र सरकार ने इंडिगो को स्पष्ट निर्देश दिए, सभी लंबित रिफंड पूरे किए जाएं

केंद्र सरकार ने इंडिगो को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरे किए जाएं। इसके अलावा, यात्रियों से किसी प्रकार का रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि कोई एयरलाइन इस आदेश का पालन नहीं करती है, तो इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो की लापरवाही का पूरे सिस्टम पर असर पड़ा है और सरकार ने इसे लेकर सख्त रवैया अपनाया है। एयरपोर्ट पर स्थित कर्मचारी और प्रशासन भी यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लगातार पूछताछ के बीच तनाव में दिखाई दिए। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अधिकारियों ने कहा कि सिस्टम को जल्द स्थिर करना प्राथमिकता है। यह अव्यवस्था यह दिखाती है कि जब किसी बड़ी एयरलाइन का संचालन फेल होता है, तो पूरे देश में यात्रा प्रभावित होती है और आम लोगों की योजनाएं बाधित हो जाती हैं। इंडिगो के इस ऑपरेशन फेलियर ने यात्रियों की रोजमर्रा की जिंदगी में गंभीर असर डाला है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में लोगों ने सोशल मीडिया पर लगातार अपनी शिकायतें दर्ज कराई, एयरपोर्ट पर तनाव और अफरातफरी देखी गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि अब इंतजार की सीमा पूरी हो चुकी है, और एयरलाइन को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। यात्रियों को न केवल उनके पैसों का सही रिफंड मिलेगा, बल्कि किसी प्रकार की अतिरिक्त चार्जिंग से भी बचाया जाएगा। इस पूरी घटना ने यह भी दिखाया कि भारतीय हवाई अड्डे आमतौर पर सुव्यवस्थित और समयबद्ध रहते हैं, लेकिन जब किसी बड़ी एयरलाइन का सिस्टम फेल होता है, तो हवाई यात्रा में व्यवधान और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिलता है। इंडिगो की लगातार पांचवें दिन खराब ऑपरेशन स्थिति ने न केवल यात्रियों की नाराजगी बढ़ाई है, बल्कि एयरलाइन और सरकार दोनों पर भी दबाव डाला है। देश के एयरपोर्टों पर यह भीड़ और तनाव केवल ऑपरेशनल फेलियर की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों यात्रियों की बेबसी और थकान का भी सच है, जो हर घंटे यह सोचते रहे कि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश और डेडलाइन तय कर दी है, लेकिन इंडिगो की लापरवाही ने यात्रियों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। इस पूरे संकट ने यह भी उजागर किया है कि यात्रियों के हित में तत्काल और सख्त कदम उठाना कितना जरूरी है। इस तरह, इंडिगो की पांच दिनों से लगातार खराब ऑपरेशन स्थिति ने देशभर के एयरपोर्टों को हाहाकार की स्थिति में डाल दिया है। यात्रियों की परेशानी, लंबी कतारें, फ्लाइट कैंसिलेशन और लेट होने की संख्या ने हवाई यात्रा के सामान्य अनुभव को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और जयपुर एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर देखा गया, जहां लंबी कतारों और फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण यात्रियों का हाल बेहाल रहा। केंद्र सरकार ने सख्त हस्तक्षेप किया है और रिफंड डेडलाइन तय की है, लेकिन अब सवाल यह है कि इंडिगो कितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगी और हवाई यात्रा में स्थिरता वापस ला पाएगी। यह संकट सिर्फ ऑपरेशन फेल का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय विमानन व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा, समय की पाबंदी और एयरलाइन जिम्मेदारी का भी आईना है। इंडिगो के सिस्टम फेल और सरकार के अल्टीमेटम के बीच अब देशभर के हवाई अड्डे और यात्रियों की नजरें इस पर टिकी हैं कि कब तक यह स्थिति सामान्य होगी और कितनी जल्दी यात्रियों की परेशानियों का समाधान होगा।

नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा नए पूर्ण डयूटी समय सीमा नियम लगाने के बाद हुई स्थिति

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों उड़ान बंद होने और देरी की समस्या से जूझ रही है। इसके पीछे कई मुख्य कारण सामने आए हैं। सबसे बड़ा कारण नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा लागू किए गए नए पूर्ण डयूटी समय सीमा नियम हैं। इन नियमों के तहत पायलट और क्रू के लिए डयूटी और आराम की सीमा तय की गई है। इससे इंडिगो को पूरे नेटवर्क में पर्याप्त क्रू उपलब्ध कराने में दिक्कत आई है। इसके अलावा, एयरलाइन ने नए नियम लागू होने के समय पायलट और कर्मचारी की योजना और रोस्टर समय पर अपडेट नहीं किया। परिणामस्वरूप कई उड़ानें बिना पायलट या क्रू के उड़ान भरने में असमर्थ रहीं।

तकनीकी खराबियां, हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़, मौसम की अस्थिरता और यात्रियों की अचानक बढ़ी मांग ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया। इन सभी कारणों के चलते इंडिगो की उड़ानों का समय पर संचालन प्रभावित हुआ है और यात्रियों को उड़ान बंद होने और देरी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो की उड़ानों में अव्यवस्था के पीछे नए नियम, क्रू की कमी, तकनीकी व मौसम संबंधी समस्याएं और हवाई अड्डों पर दबाव मुख्य कारण हैं।

उत्तराखंड में इंडिगो की उड़ानों में अव्यवस्था, तीन फ्लाइट्स कैंसिल होने से परेशान यात्री

उत्तराखंड में शनिवार को इंडिगो एयरलाइन ने अपनी तीन उड़ानें कैंसिल कर दी। इनमें देहरादून से दिल्ली, भुवनेश्वर और लखनऊ के लिए उड़ानें शामिल हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस संबंध में जानकारी दी। देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट से इंडिगो की कुल 9 उड़ानें निर्धारित थीं, जिनमें से केवल एक उड़ान ही समय पर आ पाई है। यात्रियों को एयरलाइन की ओर से रिफंड और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सूचित किया गया है। इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। विशेषकर दिल्ली, भुवनेश्वर और लखनऊ जाने वाले यात्री अपनी उड़ानों के विलंब या कैंसिल होने के कारण तनाव में दिखे। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि इंडिगो की इस स्थिति के कारण यात्रियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उन्हें समय-समय पर जानकारी प्रदान की जा रही है। इस बीच यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे उड़ान के समय और स्थिति की जानकारी के लिए इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट या एयरलाइन के कस्टमर केयर नंबर से लगातार अपडेट लेते रहें।

साल 2006 में शुरू होने वाली इंडिगो भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन है

इंडिगो की शुरुआत 4 अगस्त 2006 में हुई थी। इंटरग्लोब एविएशनके स्वामित्व वाली यह एयरलाइन आज भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन बन चुकी है। देश के भीतर और विदेश के गंतव्यों तक इंडिगो की उड़ानें संचालित होती हैं। वर्तमान में इंडिगो का नेटवर्क लगभग 85 घरेलू और 32 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक फैला हुआ है। 2023 में इंडिगो पहली भारतीय एयरलाइन बनी जिसने 2,000 से अधिक रोजाना निर्धारित उड़ानें चलाने का रिकॉर्ड बनाया। इसी वर्ष, इंडिगो ने पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा दी। घरेलू हवाई यातायात में इंडिगो का बाजार हिस्सा 60.65 प्रतिशत के आसपास है। यही कारण है कि इसे "घरेलू हवाई यात्रा की प्रमुख एयरलाइन" कहा जाता है। बावजूद इसके, लगातार पांचवें दिन खराब संचालन की स्थिति ने देशभर के प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों की सुविधा, समयबद्धता और सुरक्षा को प्रभावित किया। देशभर के हवाई अड्डों पर यह दृश्य सिर्फ संचालन विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की बेबसी का भी प्रतीक है, जो हर घंटे यह सोचते रहे कि उनकी उड़ान कब भरेगी। सरकार का स्पष्ट रुख और इंडिगो की जिम्मेदारी तय करना अब यात्रियों के लिए राहत की उम्मीद बन गया है। यह घटना भारतीय विमानन व्यवस्था में जिम्मेदारी, पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करती है।

कैंपस प्लेसमेंट में धांधली:
नैतिकता और छात्र हितों का हनन

ललित गर्ग

देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों- विशेषतः आइआइटीज द्वारा 20 से अधिक कंपनियों को कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया से बाहर करना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता, पारदर्शिता और छात्र-हित संरक्षण को मजबूती प्रदान करने वाला साहसिक कदम है। इन कंपनियों ने छात्रों को ऑफर लेटर दिए, उनके परिवारों के भीतर आशा की किरण जगाई और अंतिम समय में बिना स्पष्ट कारण उन्हें रद्द कर दिया। यह केवल एक अनुबंध उल्लंघन नहीं, बल्कि छात्र के भविष्य, उसके मानसिक संसार और उसके सामाजिक विश्वास पर सीधा प्रहार है। आइआइटी, एनआइटी और शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाना किसी विद्यार्थी की दीर्घकालिक मेहनत और प्रतिभा की पहचान है। प्लेसमेंट और ऑफर लेटर केवल नौकरी नहीं, बल्कि परिवार के लिए भविष्य की सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं। ऐसे में जब कंपनियां अचानक अपना वादा तोड़ देती हैं, तो विद्यार्थी केवल पेशेवर नुकसान नहीं झेलते, बल्कि मानसिक तनाव, अविश्वास और सामाजिक दबाव से भी गुजरते हैं। यह उनके मनोबल को कमजोर करता है और उनकी योग्यता के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इस तरह की स्थितियां बनना न केवल भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर एक चिन्ताजनक दाग है, बल्कि सरकार एवं कम्पनियों पर छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का शर्मनाक द्योतक है। निस्संदेह वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता, मंदी, छंटनी और बाजार उतार-चढ़ाव से जूझ रही है। लेकिन इन चुनौतियों का भार छात्रों के कंधों पर डालना किसी मानवीय, पेशेवर या नैतिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। विश्वविद्यालय किसी प्रयोगशाला की तरह नहीं हैं जहां विद्यार्थियों को जोखिमपूर्ण स्थति में डालकर कंपनियां प्रयोग चलाती रहें। आइआइटीज का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि छात्रों के भविष्य और सम्मान से खिलवाड़

सहन नहीं किया जाएगा तथा संस्थान उनके साथ खड़ा रहेगा। यह कदम उच्च शिक्षा की गरिमा और राष्ट्रीय प्रतिभा के सम्मान की पुनर्स्थापना है। यह अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी मार्गदर्शक हो सकता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि सुरक्षित और विश्वसनीय भविष्य प्रदान करना है। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना ही छात्रों के लिये एक बड़ी चुनौती होती है, छात्र इन संस्थानों के भारीभरकम आर्थिक बजट को किसी तरह पूरा करते हैं, इसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है तो यह उनके जीवन को अंधकारमय बना देने जैसा है। देश के अधिकांश शिक्षण संस्थानों में प्लेसमेंट व्यवस्था उतनी सुदृढ़ और पारदर्शी नहीं है, जितनी आइआइटीज में। हजारों छात्र नौकरी व अवसर की आशा में बैठते हैं और कुछ कंपनियां इस स्थिति का दुरुपयोग कर "ऑफर रद्द करने" की प्रवृत्ति अपनाती हैं। अब आवश्यक है कि अन्य विश्वविद्यालय भी कड़ी और अनुशासित प्लेसमेंट नीति अपनाएं, कंपनियों के व्यवहार का रिकॉर्ड रखें और बार-बार गलती करने वालों को ब्लैकलिस्ट करें। यदि शीर्ष विश्वविद्यालय सामूहिक रूप से यह कदम उठाएं, तो कॉर्पोरेट जगत पर नैतिक अनुशासन का दबाव स्वतः निर्मित होगा। यह विषय अब केवल विश्वविद्यालय का मसला नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता बन चुका है। छात्रों की बेरोजगारी, अवसरों की अनिश्चितता और कंपनियों की बेहिसाब मनमानी देश की प्रतिभा को क्षति पहुंचा रही है। इसलिए सरकार और नियामक संस्थाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि प्लेसमेंट अनुबंध और कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए, कंपनियों के व्यवहार का राष्ट्रीय डाटा रिकॉर्ड विकसित करे, गलती करने वाली कंपनियों को सरकारी परियोजनाओं और प्रोत्साहनों से वंचित करे तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करे। छात्रों के संरक्षण हेतु बैकअप प्लेसमेंट समर्थन, आर्थिक सहायता और अनुबंधिक सुरक्षा उपाय जैसी व्यवस्थाएं भी विकसित की जानी चाहिए, ताकि किसी छात्र का भविष्य कंपनी की मनमानी से प्रभावित न हो।

आइआइटी जैसे संस्थानों में प्रवेश पाना ही किसी भी छात्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। आइआइटी की प्लेसमेंट व्यवस्था पहले से ही काफी अनुशासित और नियमबद्ध है। कंपनियों को भाग लेने से पहले कई शर्तो का पालन करना होता है। इसके बावजूद यदि

कोई कंपनी अपने वादे से मुकरती है, तो उसे जवाबदेह ठहराया जाना आवश्यक है। क्योंकि छात्रों को जब ऐसे किसी प्रतिष्ठित कंपनी से ऑफर लेटर मिलता है, तो वह न केवल उनके कॅरियर, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य की उम्मीद बन जाता है। यदि वही कंपनी अंतिम समय में बिना ठोस वजह के ऑफर रद्द कर दे, तो यह केवल पेशेवर अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि छात्रों के साथ किया गया खुला विश्वासघात है। आज का कॉर्पोरेट जगत तेजी से बदल रहा है, उसके मूल्य और मानक बिखर रहे हैं, भारत जब दुनिया की तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब ऐसी त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों का बनना चिन्ताजनक है। इससे भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की साख एवं प्रतिष्ठा भी दांव पर लगती है, इन्हीं स्थितियों के कारण छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये अग्रसर होते हैं।

भारत ज्ञान और युवा शक्ति का देश है। उसके शीर्ष संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा तभी कायम रह सकती है जब प्लेसमेंट प्रक्रिया भरोसेमंद, सम्मानजनक और नैतिक होगी। कंपनियों को भी समझना होगा कि युवाओं के साथ अनुचित व्यवहार उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और समाज के साथ उनके संबंध कमजोर करता है। आइआइटी का यह निर्णय उन कंपनियों के लिए चेतावनी तो है ही, लेकिन शिक्षा जगत और नीति निर्माताओं के लिए अवसर भी है-एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का अवसर जहां छात्र का सम्मान एवं जीवन-सुरक्षा सर्वोपरि हो। यदि संस्थान, सरकार और समाज मिलकर स्पष्ट, कठोर और नैतिक ढांचा बनाएं तो निश्चित ही युवा प्रतिभा सुरक्षित होगी और भारत की विश्वसनीयता भी सुदृढ़ होगी। छात्र केवल डिग्री प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए आइआइटी का यह निर्णय स्वागतयोग्य है, बल्कि इसे बदलाव की दिशा में एक निर्णायक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि अन्य विश्वविद्यालय, सरकार और समाज भी इसी दिशा में आगे बढ़ें, तो निश्चित ही देश की प्रतिभा को वह सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिलेगा जिसकी वह अधिकारी है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में प्लेसमेंट के नाम पर कंपनियों द्वारा छात्रों के साथ की जाने वाली धांधली, छल-प्रपंच और वायदाखिलाफी आज एक गम्भीर चिंता का विषय है। अनेक बार छात्रों को आकर्षक वेतन, उज्ज्वल भविष्य और स्थायी नौकरी के सपने दिखाए जाते हैं, किंतु चयन प्रक्रिया के बाद उन्हें कम वेतन, अस्थायी अनुबंध, असंगत कार्यक्षेत्र या नियुक्ति टालने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह विश्वासघात केवल छात्र का नहीं, बल्कि संस्थान और शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का नुकसान है। अतः भारत सरकार को एक स्पष्ट, कठोर और पारदर्शी नीति बनानी चाहिए, जिसमें प्लेसमेंट देने वाली कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो, अनुबंधित शर्तों का पालन अनिवार्य हो तथा उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान हों। इससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा, शिक्षा-प्रणाली की गरिमा बचेगी और उद्योग जगत में विश्वसनीयता एवं नैतिकता की संस्कृति विकसित होगी। इस दृष्टि से आइआइटी प्रशासन का ताजा निर्णय कि ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, एक सख्त संदेश देता है कि छात्रों का सम्मान, कैरियर और भविष्य सर्वोपरि है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दुनियाभर में अपनी पहचान रखने वाले आइआइटी और एनआइटी जैसे संस्थान इस तरह की नीति अपनाएं। इससे कंपनियों पर नैतिक और व्यावसायिक अनुशासन बनाए रखने का दबाव बनेगा। साथ ही छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि अन्याय होने पर संस्थान उनके साथ खड़ा होगा। इसके अलावा सरकार और उच्च शिक्षा नियामक संस्थाओं को भी इस दिशा में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। एक ऐसी केंद्रीय व्यवस्था विकसित की जा सकती है, जिसमें ऑफर लेटर रद्द करने जैसी घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जाए और बार-बार ऐसा करने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। यह कदम न केवल छात्रों की रक्षा करेगा, बल्कि प्लेसमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करेगा।

बीस करोड़ की शादी में हुआ हादसा और हमारी सीख

मनोज श्रीवास्तव
उपनिदेशक, प्रभारी विधान सभा मीडिया सेंटर, देहरादून

शादी की तैयारी चल रही थी, खास रिश्तेदार के बेटी की शादी थी। शादी के आमंत्रण की जानकारी फोन और डिजिटल कार्ड द्वारा प्राप्त हुआ। शादी के प्रति हमारा उत्साह था। उत्साह को लेकर सरकारी छुट्टी लेकर दो दिन के लिये फुल इंजायमेंट हेतु शादी स्थल के लिये सुबह वन्दे भारत से दिल्ली के लिये निकल पडे। हमें डिजिटल कार्ड द्वारा बताया गया था कि शादी आयोजन स्थल गुडगॉव में है, जहा हम मेट्रो तक आसानि से आ जा सके लेकिन पता लगा कि शादी स्थल दिल्ली से 70 किलो मीटर दूर गुड़गांव के आगे मेवात जिला के हसन पुर गांव में जाना है। दिल्ली से कुल रास्ता लगभग 3 से 4 घंटे का था। सुबह का निकलकर शाम को 03 बजे एक 05 स्टार होटल में अंत मे पहुंच गये।

पहुंचते ही होटल के दरबान स्वागत हेतु हमारा सभी सामान ले लिया, और कहा कि यह सामान आपको रूम में मिल जायेगा। मैं भी पूरे ठाठ से रिसेप्शन पर पहुंचा और पूछा कि मेरा रूम कहां है। बताया गया कि आपका रूम यहा नहीं है। पुनः पूछने पर कि मेरा रूम इसके अलावा कहां है तो पता लगा कि उससे कम स्टार वाले होटल में जो वहां से लगभग 02 किलोमीटर दूर है वहां पर मेरा रूम होगा। यहां पर पहली मैंने गलती की थी कि अपनी टैक्सी छोड़ दी थी जो कि हमें हमेशा रखना था। बताया गया की इंवेटमनेजमेंट की गाड़ी आपको कम स्टार वाले होटल में छोड़ेगी। जद्दोजहद के बाद इंवेट मैनेजमेंट की गाड़ी ने हमको होटल छोड़ा लेकिन सामान उस ड्राइवर ने हमें दिये बिना वापस लेकर चला गया। नाराजगी व्यक्त करने पर 20 मिनट बाद पुनः हमें अपना सामान मिला। दूसरे कम स्टार के होटल के रिसेप्शन पर पता लगा कि मेरा रूम यहां भी नहीं है। नाराजगी होनी स्वाभाविक थी। गुस्से में मैंने रिसेप्शन वाले से चार्ट छीनकर खुद देखना चालू कर दिया तो पता लगा कि मेरा रूम वहीं पर था।

इसके बाद मैं अपने रूम पर रिलेक्स होकर लेट गया। तीव्र भूख के कारण कुछ खाने का ऑर्डर किया। बताया गया कि इस समय खाना बंद है आपको पेमेंट पर कुछ मिलेगा। मैंने 750 रू. के पकोड़े मंगा कर अपनी भूख आंशिक रूप से शांत किया। इसके बाद पुनः निराश होकर बेड पर बैठ गया, क्योंकि शादी की गतिविधियां 02 किलोमीटर दूर होनी थी। मैंने सुबह यहां से निकलने का प्लान बना लिया। यह सोचकर प्लान बनाया कि शाम को खाने के स्थान पर आन पेमेंट सूप का ऑर्डर देकर रात में सोने के बाद सुबह निकल जायेंगे। क्योंकि हमें रात का खाना भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसी दिन 04 बजे शाम को व्हाट्सअप पर मैसेज मिला कि 5 स्टार होटल ने जो कि 02 किलोमीटर दूर है वहां खाने पीने का प्रबंध है और मीका सिंह का प्रोग्राम होना है।

हमें थोड़ा राहत मिली कि वहां पर खाना तो मिल ही जायेगा और हमारे अन्य परिचित और रिश्तेदारों से भेट मुलाकात हो जाएगी। आयोजन स्थल पर पहुंचने के बाद हमने नवेद के रूप में साड़ी के साथ रखे गए 2100 रुपये के लिफाफे से एक हजार रुपये निकाल लिए और फिर एक घरेलू महिला को दे दिया। बाद में पता चला कार्यक्रम के गर्मी में हमारे साड़ी वाले पैकेट से किसी ने पैसा वाला लिफाफा निकाल लिया था।

इसके बाद कुछ खाने के लिए निकला चाट, स्नेक्स के स्टाल लगे थे लेकिन हमारी इच्छा सूप पीने की थी, सूप वाले स्टाल ने बताया अभी इसे खोलने की परमिशन नहीं मिला है। मैं फिर निराश हो गया लेकिन आधे घंटे बाद हमें सूप मिल गया। दुर्भाग्य से मेरे जीवन का यह स्वाद में सबसे खराब सूप था। चूंकि हमें मुरादाबादी दाल पसंद है, इसलिये मुरादाबादी दाल स्टाल पर गया जहा पर सामान्य मात्रा से 1/4 एक सुदर कटोरी में मुरादाबादी दाल हमें मिला, लेकिन दुर्भाग्य से स्वाद के मामले में इससे खराब दाल नहीं खाया था।

इसके पूर्व जो हमने जिस कम स्टार वाले होटल में भुगतान के आधार पर पकोड़ा खाया था। उस पकोड़े से होने वाले इंफेक्सन का असर अब 08 बजे रात में दिखने लगा। इसलिये बिना कुछ खाना खाये मैं पुनः अपने रूम में आकर सो गया। रात में हमें एक उल्टी हुई और 08 बार लूज मोशन हुए। अगले दिन सुबह अपने को सुरक्षित करने के लिये अपने चचेरे भाई के कमरे में जाकर बैठ गया। दवा इत्यादि का प्रबंध होटल में कहीं नहीं था। हमारे परिचित डॉक्टर हरिद्वार से फोन पर दवा की जानकारी मिली, परंतु दुर्भाग्य से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई मेडिकल स्टोर नहीं था। इसलिए हमारे एक अन्य चचेरे भाई जो नोएडा से शादी अटेंड करने आ रहे थे उनसे हमने एक इनोवा गाड़ी फुल टाइम के लिए लाने को कहा और साथ में दवा भी।

दूसरे दिन लगभग 01 बजे दवा और गाड़ी मिलने से पुनः मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। इस बीच में हम नमक पानी का घोल देशी स्टाइल में ले रहे थे। लूज मोशन चल रहा था। 01 बजे दवा मिलने से थोड़ी राहत मिली।

पुनः 01 मैसेज मिला आप लोग 05 बजे जमुना घाट पर 5 स्टार होटल में आ जाएं, विवाह का एक कार्यक्रम है। हम जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहते थे। जमुना घाट पर 05 बजे शाम टी स्टॉल पर ब्लैक टी मांगने पर यह कह कर मना किया गया कि

यह मेनू में नंही है, जबकि 5-7 तरह की चाय मौजूद थी। मैं 06:00 बजे शाम को इस उद्देश्य से 05 स्टार होटल छोड़ दिया कि दिल्ली में अपने भतीजे के घर पहुंच कर मूंग की खिचड़ी खा लुंगा। इस बीच में वापसी का सारा प्रोग्राम बदलकर मैंने प्लेन से अगली सुबह का टिकट अपनी सुरक्षा की दृष्टि से करवा दिया था।

शादी में जयमाला कार्ड के अनुसार समय 05:00 बजे निर्धारित था। लकिन जयमाला 06 बजे तक ना हो पाने के कारण मैं जयमाला से पूर्व 06:00 बजे निकल गया। मैंने अपने चचेरे भाइयों से कहा कि आप लोग भी चलो, तो उनका उत्तर था थोड़ी देर और रूक लेते हैं। जयमाला लेट होने की आशंका और सुबह ऑफिस छूटने का अंदेशा से उन्होंने लगभग 08:00 बजे रात खाना खाकर निकलने का फैसला किया। लेकिन खाने के स्टॉल पर जाने पर उन्हें पता लगा कि यह खाना जयमाला के बाद खुलेगा। चूंकि यह आयोजन निर्जन स्थान पर था। यहां ओला आटो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में नहीं थी। इसलिए उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट से मैट्रो तक छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन निराशा हाथ लगी। इसके बाद उन्होने होटल वाले से बात करने पर उन्हे 1500 रू. में एक टैक्सी 25 किलोमीटर दूर मैट्रो तक छोड़ी। कई जर्नी ब्रेक करके 1.30 बजे रात में ये लोग नोएडा पहुचकर खाना खा सके।

इसके पूर्व जिस टैक्सी ड्राइवर ने हमको दिल्ली छोड़ा था उसका कथन था कि ''साहब ये बड़ा अनटप्पू जगह शादी थी'' हमने पूछा क्यों ड्राइवर ने बताया साहब 10 किलोमीटर दूर में हम लोग खाने के लिए ढाबा खोजते रहे लेकिन हमें खाना नहीं मिला। इसके पूर्व होटल मैनेजमेंट ने ड्राइवर, मजदूर के लिए कोई खाने का प्रबंध नहीं रखा था।

इस घटनाक्रम का सीख यह है कि आने वाले दिनों में लोगों के पास पैसा अत्यधिक आ जाने से शादियां इसी प्रकार के इवेंट के रूप में होंगी। इवेंट का स्थल निर्जन टापू पर या रिजार्ट में होगा जिसके इर्द-गिर्द 10 किलोमीटर में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओला इत्यादि की सुविधा नहीं मिलेगी। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, मेडिकल स्टोर नहीं मिलेगा और खाने को नहीं मिलेगा। इतने दृष्टिकोण को रखकर तब अपनी पूरी व्यवस्था के साथ इस प्रकार की शादी में जाने की हिम्मत करें अन्यथा कोई हादसा हो सकता है।

प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे समन्वय और संवाद अभियान

- विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारम्भिक तैयारियां शुरु
- 2003 की मतदाता सूची से की जाएगी वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग
- हर मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे फिल्ड ऑफिसर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के कम में उत्तराखण्ड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरु कर दी गई हैं। इस चरण में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारम्भिक तैयारियां की जाएंगी, साथ ही एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके दृष्टिगत 'प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद' अभियान पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग वर्षो में इससे पूर्व 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) पूरे देश में संपादित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में वर्ष 2003 में एसआईआर किया गया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में आयोग द्वारा पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में 12 अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने बताया कि आयोग का इस पूरी प्रकिया के पीछे उद्देश्य हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना है।

'प्रत्येक मतदाता तक पंहुच, समन्वय और संवाद' अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्री एसआईआर फेज में प्रदेश की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल लगभग 40 वर्ष तक की आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे उनकी सीधे बीएलओ एप से मैपिंग की जाएगी। इसके साथ ही 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में किसी कारणवश नहीं है तो उनके माता-पिता अथवा दादा-दादी के नाम के आधार पर प्रोजनी के रुप में मैपिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची www.ceo.uk.gov.in एवं www.voters.eci.gov.in पर सर्च की जा सकती है।

राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से बीएल नियुक्त करने की अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 11733 बूथ के सापेक्ष 4155 बीएलए ही नियुक्त हैं।

हेल्प डेस्क होगी स्थापित

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि सभी जनपदों में जिलाधिकारी, ईआरओ और बीएलओ को मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद एवं ईआरओ स्तर पर एक हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है ताकि मतदाताओं को आसानी से मदद मिल सके। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास मौजूद रहे।

आर्थोपेडिक्स की किसी भी सर्जरी के बाद फिजियोथैरिपी एक्सरसाईज की अहम भूमिका

डॉ. आदित्य कीर्ति मोंगिया
MBBS DORTHO DNB MNAMS FACS
असिस्टेंट प्रोफेसर,
सुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून

समय के साथ-साथ समाज में आर्थोपेडिक समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। मांसपेशियों में कमजोरी, अर्थराइटिस, घुटनों की समस्याएं इत्यादि से आम आदमी अब तेजी के साथ रूबरू हो रहा है। आर्थोपेडिक समस्याओं के विषय में जानकारी साझा करने के लिए हमने आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. आदित्य कीर्ति मोंगिया से बात की। पेश है उनसे हुई वार्ता के कुछ अंश....

प्रशन- ज्वाइंट रिप्लेसमेंट या ज्वाइंट प्रत्योरोपण सर्जरी क्या होती है? क्या इस सर्जरी के बाद मरीज पूरी तरह से सामान्य जीवन जीने में सक्षम होता है?

उत्तर- जब हमारे ज्वाइंट में आरथारेटिस आ जाता है या ज्वाइंट की सतह घिस जाती है तब उस ज्वाइंट में दर्द रहने लगता है। उस दर्द की वजह से व्यक्ति सही तरीके से अपने रूटीन के कार्य जैसे सामान्य चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना या उतरना, सही से बैठना या बैठे से खडा होना इत्यादि नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में ज्वाइंट की सतह की सफाई करके एक कैप की मैटल का इम्प्लांट लगाया जाता है। इसको ही ज्वाइंट रिप्लेसमेंट या ज्वाइंट प्रत्यारोपण सर्जरी कहा जाता है। इस सर्जरी के बाद हमारे शरीर में जितने भी जोड होते है उनकी सतह को दर्द से राहत मिलता है और व्यक्ति अपने सारे रूटीन कार्य जैसे एक्सरसाईज करना, घूमना फिरना, सीढ़ी चढ़ना या उतरना आदि बिना किसी परेशानी के कर पाता है। ज्वाइंट के खराब होने से जितनी भी दिक्कते शरीर में आती है वे सब इस सर्जरी के बाद ठीक हो जाती है। हालांकि इस सर्जरी के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जोड़ को मजबूत बनाने के लिए उससे रिलेटिड फिजियोथैरिपी की जितनी भी एक्सरसाईज है उसको सही तरीके से फॉलो किया जाए।

प्रशन- आर्थोपेडिक्स में फिजियोथैरिपी एक्सरसाईज की क्या भूमिका होती है? इसके बारे में विस्तार से बताईये।

उत्तर- आर्थोपेडिक्स की सर्जरी के बाद सबसे ज्यादा समस्या मांसपेशियों की कमजोरियों का होना होता है। यह कमजोरी इसलिए होती है क्योकि शरीर का एक नियम है कि उसका जो भी अंग इस्तेमाल में नहीं आयेगा वह धीरे-धीरे कमजोर होता चला जायेगा। आरथेराइटिस हो या फैक्चर या अन्य कुछ भी तो उस जोड के आस-पास की जो मांसपेशियां होती है वह कमजोर हो जाती है। इन कमजोर मांसपेशियों में वापिस ताकत लाने के लिए फिजियोथैरिपी एक्सरसाईज होती है। फिजियोथैरिपी की एक्सरसाईज फिजियोथैरिपी विशेषज्ञ डॉक्टर की देख-रेख में की जाती है। जैसे-जैसे मांसपेशियों में ताकत आती जाती है वैसे-वैसे उस अंग का कार्य करना आसान होता जाता है। इसलिए आर्थोपेडिक्स से सम्बन्धित किसी भी सर्जरी के बाद फिजियोथैरिपी की एक्सरसाईज जरूर करनी चाहिए।

प्रशन-आर्थोपेडिक्स की किसी भी अंदरूनी सर्जरी में सामान्यतः प्लेट या रॉड का उपयोग होता है। ये क्या होती है और उनका क्या कार्य होता है?

उत्तर- शरीर में जब भी कोई हड्डी फैक्चर होती है तब उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। फ्रैक्चर हुई हड्डी को जोड़ने का कार्य तो हमारे शरीर का ही होता है लेकिन उसको सही जगह पकड़कर रखने के लिए हम रॉड और प्लेट का प्रयोग करते है। हड्डी जुडने का जो शुरूआती प्रोसेस है उसमें शरीर को लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। हड्डी जुडने के इस प्रोसेस में हम रॉड या प्लेट को स्क्रू के माध्यम से टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर रखते है ताकि शरीर उसको सही जगह पर जोडे। एक बार जब हड्डी पूरी तरह जुड़ जाती है, जिसमें अमूमन 3 से 6 महीने का समय लगता है, तो जो रॉड या प्लेट शरीर में डाली गई थी उसको साल या डेढ साल के बाद निकाला भी जा सकता है। रॉड और प्लेट की अलग-अलग किस्में आती है। एक होती है 316L Grade Steel और दूसरी होती है Titanium. स्टील की रॉड या प्लेट के मुकाबले टाईटेनियम की प्लेट थोड़ी महंगी होती है क्योंकि टाईटेनियम पदार्थ हड्डी से ज्यादा मैच करता है और हड्डी जैसा ही लचीला होता है।

प्रशन-क्या आर्थोपेडिक्स सर्जरी में भी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का इस्तेमाल किया जा रहा है?

उत्तर- आजकल के बदलते हुए इस समय में एआई (AI) का रोल हर जगह फैलता जा रहा है। इसी तरह से आर्थोपेडिक्स सर्जरी में भी एआई (AI) का अब काफी प्रयोग होना शुरू हो गया है। पहला प्रयोग तो जैसे सभी जानते है कि एक रोबोट के तौर पर होता है जो हम ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में यूज कर रहे है। रोबोट को यूज करते हुए ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना काफी आसान हो गया है और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे सामने आ रहे है। इसके साथ ही Rayban Meta Glasses को यूज करके हम सारी चीजे एआई (AI) के माध्यम से बेहतर देख और कर पाते है। इसके साथ ही इनको रिकार्ड करके मरीज को देना भी आसान हो गया है। अब धीरे-धीरे एआई (AI) का प्रयोग और बढ़ता जा रहा है। हम ऑपरेशन करने से पहले ही डिसाईड कर लेते है कि ज्वाइंट में कौन से साईज का सामान लगना है या कोई हड्डी टूटी है तो उसको सिटी स्कैन या एमआरआई के साथ फीड करके देख लेते है कि कौन से किस्म की रॉड या प्लेट सुटेबिल होगी और उसकी तैयारी करके हम बेहतर सर्जरी कर पाते है। इस प्रकार एआई (AI) का प्रयोग अब धीरे-धीरे आर्थोपेडिक्स में भी बढ़ता जा रहा है।

हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड गुणवत्ता–आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और हेल्थकेयर स्किल डेवलपमेंट का मॉडल बनकर उभरे- डॉ. आर. राजेश कुमार

• स्वास्थ्य शिक्षा में नई क्रांति की शुरुआत-10 श्रेणियों में 56 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को दी गई मान्यता, पैरामेडिकल शिक्षा को मिलेगा नया स्वरूप

• नए विषयों से बढ़ेगा युवाओं का दायरा, मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवाएँ, पैरामेडिकल तथा एलाइड हेल्थ शिक्षा में आएगी एकरूपता, पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी

उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक, पारदर्शी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों और दूरदर्शी नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम-2021 के तहत उत्तराखंड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन की प्रक्रिया को तेजी देने हेतु सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने की। बैठक की शुरुआत में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और आपदा-संवेदनशील राज्य में आधुनिक, प्रशिक्षित और प्रमाणित एलाइड हेल्थ वर्कफॉर्स का विकास अत्यंत आवश्यक है। परिषद के गठन से न केवल शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि देशभर में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में उत्तराखंड अग्रणी भूमिका निभाएगा।

परिषद गठन पर विस्तृत चर्चा, चयन समिति के गठन का निर्णय

बैठक में परिषद के गठन, उसकी संरचना, भविष्य की आवश्यकताओं और कार्य प्रणालियों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। यह तय किया गया कि परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए "तलाश-सह-चयन समिति" बनाई जाएगी, जो निर्धारित योग्यताओं और अनुभवों के आधार पर नामों का चयन करेगी। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिषद के सुचारू संचालन के लिए प्रारंभिक बजट, कार्यालय संरचना, तकनीकी सहायता और मानव संसाधन की उपलब्धता तुरंत सुनिश्चित की जाए, ताकि परिषद अपने दायित्वों का निर्वहन शीघ्र आरंभ कर सके।

वर्तमान में राज्य में पैरामेडिकल शिक्षा

उत्तराखंड पैरामेडिकल अधिनियम-2009 और स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से संचालित होती है। यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 22 विषयों के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रीय अधिनियम लागू होने के बाद इन सभी पाठ्यक्रमों को और अधिक मानकीकृत, रोजगारोन्मुख, और कौशल आधारित बनाया जाएगा। नए अधिनियम में कुल 10 श्रेणियों में 56 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मान्यता दी गई है। इससे विद्यार्थियों को न सिर्फ व्यापक करियर अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग्यता को उच्च पहचान मिलेगी।

मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवाएँ

बैठक में विशेषज्ञों ने बताया कि अधिनियम के तहत कई नए और महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। पोषण विज्ञान, स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डायलिसिस तकनीशियन, एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन, आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन आदि। इन विषयों के शामिल होने से राज्य के युवाओं को विस्तृत करियर विकल्प, निजी और सरकारी क्षेत्र में बेहतर प्लेसमेंट, तथा शोध और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं में अवसर मिलेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड को स्वास्थ्य शिक्षा और एलाइड हेल्थ सर्वीस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेगा और भविष्य में राज्य एक "हेल्थ एजुकेशन हब" के रूप में स्थापित होगा।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान

उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़, सुगठित और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन हमारे लिए परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। इससे पैरामेडिकल तथा एलाइड हेल्थ शिक्षा में एकरूपता आएगी, पाठ्यक्रमों का मानकीकरण होगा और पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी बनेगी। नए अधिनियम के तहत कई उभरते विषय और विशेषज्ञताएँ शामिल होंगी, जिससे युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर मिलेगा। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड गुणवत्ता-आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और हेल्थकेयर स्किल डेवलपमेंट का मॉडल राज्य बनकर उभरे।

प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर थैरेपी असाध्य रोगों से मुक्ति पाने का बेहतर उपायः डॉ. केके शर्मा

गंगा मैती परिवार ने कैंप लगाकर लोगों को किया प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक

उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून, उत्तराखंड की ओर से दिनांक 28-30 नवम्बर, 2025 के बीच ग्राफिक एरा यूनिर्वसिटी देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन एवं 20वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें गंगा मैती परिवार संस्था, नई दिल्ली द्वारा प्रो. (डॉ.) के. के. शर्मा जी, पूर्व एचओडी, पी.जी. मेडीकल कॉलेज, हरिद्वार की अध्यक्षता में नि:शुल्क आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी एवं एक्यूप्रेशर पद्धति से असाध्य रोगों के निदान हेतु उपचार किया गया साथ ही मां गंगा को निर्मल रखने सम्बधी जागरूकता व प्राचीन समय के उपयोगी पात्र जैसे तांबा, पीतल, मिट्टी आदि के उपयोग संबंधी लोगों को जागरूक किया।

कैम्प का उदघाटन प्रो. (डॉ.) दुर्गेश पंत, महानिदेशक, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एव एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून की गरिमा मय उपस्थिति में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रीमा पंत के कर कमलों द्वारा किया गया जिसमें डॉ. कुंवर राज अस्थाना, डॉ. पीयूष गोयल व अन्य गणमान्य व्यक्ति वैज्ञानिक उपस्थित थे।

शिविर में देश-विदेश, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं, विभागों से आए नागरिको, विद्यार्थियों अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों आदि ने भाग लिया।

डॉ. दीपा एन. मोठघरे पूर्व अधिकारी, नीति आयोग जो कि 30 वर्षो से नि: शुल्क एक्युप्रेशर द्वारा स्वास्थ की सेवाएं दे रही है व मरणोपरान्त भी देह दान का संकल्प लिया है तीन दिवसीय कैंम्प में लगभग 150 नागरिकों को सरवाईकल, साइटिका, घुटना, कमर दर्द, श्वास रोग का चमत्कारिक ईलाज किया व बीपी, शुगर, थायराईड, हड्डी रोग, स्त्री, पुरुष बांझपन आदि रोगो के स्थाई निदान के लिए उपचार किया व स्थाई समाधान के लिए प्रशिक्षण भी दिया जिसमें देव पाल सिंह नीति आयोग द्वारा विशेष सहयोग किया गया व महेश चन्द नौटियाल जी पूर्व अधिकारी सम्पदा मंत्रालय ने शिविर की व्यवस्था में नि:स्वार्थ सहयोग किया एवं आदर्श जीवन शैली अपनाए जाने पर लोगो को जागरूक किया।

गंगा मैती संस्था के अध्यक्ष आर. डी. चमोली जी ने देव भूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षणता, भौगोलिक स्थिति आदि को आगामी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखे जाने की अपील की। डिस्पोजल सामग्री, प्लास्टिक आदि के उपयोग से पर्यावरण व जीवन डिस्पोजल हो रहा है। प्लास्टिक का उपयोग न करना, गंगा नदी को स्वच्छ रखना, पारम्परिक जीवन शैली धातुपात्रों जैसे पीतल तांबा मिट्टी पात्रों का आदि का उपयोग के सम्बन्ध में शिविर में उपस्थित सभी को जागरूक किया व देवभूमि उत्तराखंड के प्रशासन से अपील की कि विद्यालयों में स्वास्थ्य, पर्यावरण, धातुविक पात्रों के उपयोग, पौराणिक जीवन शैली अपनाना आदि के पठन संबंधित व्यवस्था स्कूल पाठयक्रम में कराई जाए ताकि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण व संस्कृति को संरक्षित रखकर नवीन पीढ़ी के सुखद जीवन के लिए खुद को समर्पित किया हमारी आगामी पीढ़ी भी लाभांवित हो व संस्कृति की मूलाधार से जुडकर स्वस्थ भारत व समृद्धि भारत का निर्माण हो सके।

संस्था के मुम्बई क्षेत्र के प्रमुख प्रवीण ठाकुर जी सहयोगी सहित आर के महापात्रा, स्लोचना कपिल, मीनाक्षी भट्ट, मनोज भट्ट, प्रहलाद अधिकारी आदि का विशेष योगदान रहा।

नीति आयोग, नई दिल्ली के कल्याण अधिकारी टी.वी. सिंह जो पिछले दशको से नि:स्वार्थ एक्यूप्रेशर कैम्पो को आयोजित कराने व स्वास्थ्य के प्रति लोगो में जागरूकता व पर्यावरण संरक्षण कार्यो में योगदान दे रहे है उनके द्वारा स्वास्थ के प्रति जागरूकता, जीवन शैली में परिवर्तन, मोबाईल का स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि व्याख्यान से लोगो को जागरूक व लाभान्वित किया। उनकी अग्रिणी भूमिका रही व उनका सहयोग

स्मरणीय रहा।

यूकॉस्ट के वैज्ञानिक मंडल डॉ. पियूष गोयल, डॉ. डी.पी. उनियाल, डॉ. राजेन्द्र सिंह राणा, डॉ. आशुतोष मिश्रा, पियूष जोशी, डॉ. मनोज सिंह रावत, डॉ. मनमोहन सिंह रावत, डॉ. अमित पोखरपाल, डॉ. नौटियाल, सुभाष नेगी, डॉ. कुवंर राज अस्थाना सम्पादक (दिव्य हिमगिरी) देहरादून व देवेन्द्र सिहं ने अपना अमूल्य समय दिया व एक्यूप्रेशर टीम की सराहना की तथा यूकॉस्ट द्वारा आस्वस्त किया गया कि भविष्य में इस चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकी आधार पर पुनः ईलाज हेतु स्थान दिया जाएगा व विद्यालयों में समय-समय पर जागरूकता अभियान कराया जाएगा।

ग्राफिक एरा यूनिर्वसिटी, विज्ञान केन्द्र, अन्य क्षेत्रो व देश विदेश से आए मेहमानों, अधिकारियों, कर्मचारियों, बच्चों, विशिष्ट व्यक्तियों ने एक्यूप्रेशर पद्धति के चमत्कारिका लाभों को महसूस किया व भविष्य के लिए प्रशिक्षण लेकर खुद को अच्छे स्वास्थ के लिए तैयार किया तथा शिविर को अपने-अपने क्षेत्रो में लगाने के लिए टीम से आग्रह किया। यूकॉस्ट द्वारा डॉ. दीपा मोठघरे, आर.डी. चमोली, टी.वी. सिंह, महेश चन्द नौटियाल को सम्मानित किया गया व सराहना की व मनोबल बढाया।

सीएसआईआर-आईआईपी द्वारा सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर छात्राओं हेतु 'जिज्ञासा' कार्यक्रम के अंतर्गत पांच दिवसीय आवासीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया

सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून द्वारा दिनांक 01 से 05 दिसंबर, 2025 तक सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर की 11वीं कक्षा की छात्राओं हेतु 'जिज्ञासा' कार्यक्रम के अंतर्गत पांच दिवसीय आवासीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस आवासीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किए जा रहे वास्तविक वैज्ञानिक कार्य का अवलोकन तथा उसमें प्रतिभागिता करने का अवसर प्रदान करना है। यह संस्थान में वर्ष भर में आयोजित किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक अंग है।

इस 5 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम का उद्घाटन 1 दिसंबर 2025 को किया गया। डॉ. आरती, जिग्यासा समन्वयक, सीएसआईआर-आईआईपी, देहरादून ने समग्र कार्यक्रम के बारे में छात्रों को विस्तृत जानकारी दी। डॉ. कमल मौर्य ने छात्रों को जिग्यासा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों के विषय में जानकारी दी। डॉ. उमेश कुमार ने सीएसआईआर-आईआईपी के इतिहास एवं समग्र अनुसंधान कार्यो एवं के बारे में प्रस्तुति दी।

इस आवासीय कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को दो-दो के समूहों में विभाजित किया गया तथा उन्हें प्रयोगात्मक गतिविधियों हेतु विशिष्ट प्रयोगशालाओं से जोड़ा गया, जिससे कि उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया जा सके। इन प्रयोगशालाओं में डॉ. सुनील कु. सुमन की जैव रसायन तथा जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला; डॉ. बिपुल सरकार की उत्प्रेरक विबहुलकीकरण प्रयोगशाला; डॉ. ओ. पी. खत्री की एसएसटी प्रयोगशाला; डॉ. अंकुर बोरदोलोई की उच्च-ताप उच्च दाब प्रयोगशाला; डॉ. उमेश कुमार की बहुलक पदार्थ क्षेत्र/प्रयोगशाला शामिल थीं, जिनमें छात्रों ने विज्ञान के विषय में सीखते हुए प्रयोगशाला के नियमित कार्यों में भाग लिया। इस दौरान छात्रों को सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों एवं तकनीकी अधिकारियों के साथ चर्चा करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे अधिशोषण एवं झिल्ली पृथक्करण प्रयोगशाला, उन्नत कच्चा तेल अनुसंधान केंद्र, विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला, बायोजेट ईंधन प्रयोगशाला, जैवईंधन एस्टरीकरण प्रयोगशाला, सामग्री संसाधन दक्षता प्रभाग तथा अपशिष्ट प्लास्टिक से ईंधन तथा रसायन प्रायोगिक संयंत्र का भी दौरा किया। 5 दिसंबर, 2025 को संस्थान के निदेशक डॉ. हरेन्द्र सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने अपने सम्बोधन में प्रतिभागी छात्राओं को वैज्ञानिक अनुसंधान में बढ़-चढ़ कर भाग लेने तथा इसके द्वारा भारत के सामाजिक, वैज्ञानिक और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया एवं उन्हें प्रतिभागिता प्रमाणपत्र वितरित किए। इस अवसर पर छात्राओं ने 5-दिन के इस आवासीय कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर अपनी प्रस्तुतियां भी दीं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉ. अंकुर बोरदोलोई, डॉ. उमेश कुमार, डॉ. कमल कुमार, डॉ. ज्योति पोरवाल, डॉ. दीपेंद्र त्रिपाठी, डॉ. प्रदीप त्यागी, डॉ. रघुवीर सिंह, सपना, प्रदीप सिंह पुंडीर, संजय मौर्य, गोकुल, अजय पॉल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. आरती, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक इस कार्यक्रम की समन्वयक थीं।

पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया

तराई क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग और आधारभूत संरचना की दर्जनों घोषणाएँ

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में पंडित शुक्ला जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और शिलापट्ट का अनावरण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं तराई क्षेत्र के संस्थापक पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर रुद्रपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रांगण में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके जीवन परिचय पर आधारित शिलापट्ट का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित राम सुमेर शुक्ल राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण के प्रतीक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश, समाज और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बताया कि छात्र जीवन से ही पंडित जी की राष्ट्र सेवा की भावना अतुलनीय थी। वर्ष 1936 में मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत का मुखर विरोध कर पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। बाद में गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने कानून की प्रैक्टिस छोड़ स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। अनेक बार जेल जाने और यातनाएँ झेलने के बावजूद उनका साहस कभी नहीं डिगा। 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान युवाओं को संगठित कर उन्होंने आंदोलन को नई दिशा दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी पंडित शुक्ल ने किसानों, स्वतंत्रता सेनानियों और तराई क्षेत्र के विकास को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। तराई कॉलोनाइजेशन योजना के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने तराई क्षेत्र के विकास की मजबूत नींव रखी। आज रुद्रपुर और तराई का जो स्वरूप दिखाई देता है, वह उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पंडित जी की इसी विरासत को आगे बढ़ाने में उनके पुत्र तथा मेरे मित्र राजेश शुक्ल निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। ऊधमसिंह नगर और रुद्रपुर क्षेत्र में सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। श्रद्धेय पं. राम सुमेर शुक्ल के नाम पर रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी जारी है। लगभग 590 करोड़ रुपये की लागत से रुद्रपुर बाईपास का निर्माण, खटीमा-टनकपुर और गदरपुर-जसपुर को जोड़ने वाली चार लेन सड़कों का निर्माण तथा 55 करोड़ रुपये की लागत से मानूनगर-गदरपुर-दिनेशपुर-हल्द्वानी मोटरमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि रुद्रपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, नई सिग्नल लाइनें, दो रेल ओवरब्रिज, मास्टर ड्रेनेज प्लान की मंजूरी, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स का निर्माण, 15 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और 17 करोड़ की लागत से एडवांस कूड़ा प्रबंधन प्लांट का कार्य भी जारी है। उन्होंने कहा कि किच्छा में 351 करोड़ रुपये की लागत से एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है और पंतनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। गदरपुर और खटीमा में बाईपास, खटीमा व किच्छा में आधुनिक बस अड्डे तथा रुद्रपुर, गदरपुर और चकरपुर में खेल सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर और पंतनगर में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना क्षेत्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खुरपिया में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि जमरानी बांध परियोजना को पुनः प्रारंभ किया गया है, जिससे तराई क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई की स्थायी सुविधा मिलेगी। साथ ही, हाल ही में गन्ना किसानों के हित में समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का 'विकल्प रहित संकल्प' तराई क्षेत्र को एक आधुनिक, विकसित और समृद्ध क्षेत्र बनाना है। पंडित राम सुमेर शुक्ल का यह स्वप्न सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है और इसे साकार करने के लिए सभी प्रयास जारी रहेंगे।

कार्यक्रम संयोजक एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में पंडित राम सुमेर शुक्ल ने तराई को बसाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने कहा कि आज एम्स, मेडिकल कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल स्मार्ट पार्क जैसी परियोजनाएँ तराई के सुनहरे भविष्य का संकेत देती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि "धामी है तो हामी है"ख़्धामी सरकार ने यूसीसी और नकलविरोधी कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णय लेकर एक मिसाल कायम की है।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पूर्व विधायक राजेश शुक्ल के आवास पहुँचे, जहाँ उन्होंने उनकी माताजी से आशीर्वाद लिया और भोजन ग्रहण किया।

कार्यक्रम में विधायक शिव अरोरा, मेयर विकास शर्मा, दीपक बाली, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, फरजाना बेगम, खातिब मलिक, मंजीत सिंह, उत्तम दत्ता, मुकेश कुमार, गदरपुर नगरपालिका अध्यक्ष मिंटू गुम्बर, सचिन शुक्ला, नगर पंचायत दिनेशपुर की अध्यक्ष मंजीत कौर, पंडित राम सुमेर शुक्ल मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश शुक्ला, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

"साइबर भारत सेतु: ब्रिजिंग स्टेट्स, सिक्योरिंग भारत" विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय अभ्यास कार्यक्रम देहरादून में आयोजित

साईबर सुरक्षा को लेकर देहरादून में "साइबर भारत सेतु: ब्रिजिंग स्टेट्स, सिक्योरिंग भारत" विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय अभ्यास कार्यक्रम का गुरूवार को शुभारंभ हो गया है। साईबर सुरक्षा के प्रति लचीलापन क्षमता को सुदृढ़ करने तथा अंतर-विभागीय समन्वय को बढ़ावा देने के साथ ही साइबर संकटों के प्रभावी प्रबंधन हेतु समग्र तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से सीईआरटी-उत्तराखंड तथा आईटीडीए द्वारा, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

सिविल सेवा संस्थान देहरादून के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आईटीडीए उत्तराखंड के निदेशक श्री आलोक पाण्डे ने कहा कि साईबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य उत्तरोत्तर अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। लिहाजा साईबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए राज्य के सभी विभागों और संस्थानों को गंभीरता के साथ पूरी तैयारी रखनी जरूरी है। साईबर संकटों की जानकारी और उनसे निपटने के उपायों के लिए इस तरह के आयोजनों को अत्यधिक उपयोगी बताते हुए श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य में साईबर सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम के पहले दिन विशेषज्ञों ने भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉस टीम (सीईआरटी-इन) की भूमिका और उसके द्वारा साईबर सुरक्षा के संबंध में की गई पहलों की जानकारी देने के साथ ही, उत्तराखंड में साईबर सुरक्षा की चुनौतियां और अवसर पर विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर लचीली साईबर संकट प्रबंधन योजना के निर्माण के संबंध में कार्यशाला का आयोजन करने के साथ ही साईबर खतरों एवं हमलों के तौर-तरीकों तथा इनसे बचाव के उपायों, साईबर सुरक्षा की चुनौतियों व एहतियातों और साईबर संकट प्रबंधन के उपायों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई।

कार्यक्रम के पहले दिन आयोजित विभिन्न सत्रों में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संस्थान सीईआरटी-इन के वैज्ञानिक राजेश पोखरियाल, शशांक गुप्ता, सब्यसाची जेना, राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव कमलेश मेहता, आईटीडीए उत्तराखंड के एजीएम कमलेश अरूण, आशीष उपाध्याय, ट्रेंड माईक्रो के प्रतिनिधि अंकित आदि विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए साईबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर उपयोगी जानकारी दी।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न विभागों एवं संथानों 150 से भी अधिक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों, आईटी विशेषज्ञों एवं साइबर सुरक्षा प्रशासकों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है।

डॉ. नरेश बंसल ने सदन मे प्रश्नकाल मे नशे की बढ़ती मांग व उसकी प्रभावी रोकथाम हेतु अभियान का लोकहित का प्रशन उठाया

डॉ. नरेश बंसल ने तारांकित प्रश्न संख्या-32 मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम (नशा मुक्त भारत अभियान) मे पुछा कि क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 2025 के बाद नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबी) के तीसरे चरण के लिए निर्धारित नए परिणाम आधारित लक्ष्य क्या हैं:-

(ख) लक्षित नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबी) हस्तक्षेप के लिए उच्च जोखिम वाले जिलों की पहचान करने हेतु मंत्रालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किस प्रकार कर रहा है।

(ग) क्या सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले सभी नशा मुक्ति केंद्रों के लिए अनिवार्य प्रमाणन प्रक्रिया लागू की गई है।

(घ) मंत्रालय किस प्रकार से कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के माध्यम से स्वस्थ हुए व्यक्तियों को मुख्य धारा में वापस लाने का कार्य कर रहा है और

(ङ) नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के पुनर्निमाण की वर्तमान स्थिति क्या है?

जिसका लिखित उत्तर माननीय मंत्री श्री विरेन्द्र कुमार ने सदन के पटल पर रखा और बताया कि:

उत्तर:- (क) नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के 5 वर्ष पूरे होने के समारोह के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में नागरिकों को मोबिलाइज करने के लिए, एक राष्ट्रीय अभियान (1 अगस्त, 2025 से नवंबर, 2025 तक) आयोजित किया गया जिसके दौरान प्रतिस्पर्धी और भागीदारी गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई जिसके जरिये 6.5 करोड से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया। जागरूकता सृजन गतिविधियों की गति को आगे भी बनाए रखने हेतु अगस्त, 2025 के बाद एनएमबीए के लिए नए परिणाम आधारित लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:-

- नशा मुक्त भारत अभियान के युवाओं/मास्टर स्वयंसेवकों को सशक्त बनाना, उनको प्रशिक्षण देना और उनकी क्षमता को बढ़ाना।
- साक्ष्य आधारित सामग्री के साथ आईईसी साधनों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना।
- संवेदनशील और जोखिम वाले समूहों के लिए लक्षित हस्तक्षेप दृष्टिकोण।
- निरंतर प्रयास करने की दृष्टि से नए आस्था-आधारित/आध्यात्मिक संगठनों की भागीदारी।
- संबंधित मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयों सहयोग और समन्वय।
- गुणवत्तापूर्ण व्यसन-मुक्ति, उपचार, पुनर्वास और टेलीमेडिसिन सेवाएं।

(ख) इस विभाग ने भारत में नशीले पदार्थ के दुरूपयोग के विस्तार और पैटर्न के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने का कार्य राष्ट्रीय औषध व्यसन उपचार केन्द्र (एनडीडीटीसी), एम्स को सौंपा है ताकि भारत मे विभिन्न नशीले पदार्थों का दुरूपयोग करने वाले लोगों और नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले विकारों से पीडित लोगों (हानि पहुंचाने वाले पदार्थों का उपयोग करने वाले और विभिन्न नशीले पदार्थों पर निर्भर लोगों) की संख्या के अनुपात और इसकी ठीक-ठीक संख्या का राष्ट्रीय, राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय अनुमान प्राप्त हो सके और साथ ही साथ, विशिष्ट जनसंख्या समूहों में नशीले पदार्थों के दुरूपयोग और इसके परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के तहत लक्षित हस्तक्षेपों के लिए अधिक जोखिम वाले जिलों की पहचान करने के लिए एनडीडीटीसी, एम्स द्वारा एआई-आधारित विश्लेषण किया गया है।

(ग) देशभर में नशीले पदार्थों की लत के उपचार की सुविधाओं की गुणवत्ता को मानकीकृत करने और इसमें सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार से अनुदान सहायता चाहले या प्राप्त करने वाले किसी भी संगठन के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पंजीकरण करवाएं संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र से अनुशंसा करवाएं। यह अनुशंसा केवल तभी जारी की जाती है जब संबंधित संगठन ने सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पूरी तरह अनुपालन कर लिया हो।

इसके अलावा प्रत्येक सहायता अनुदान संस्थान (जीआईए) को एनएपीडीडीआर दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय द्वारा चुने गए संगठनों से अवश्य पंजीकृत होना चाहिए। वर्तमान में, ऐसे संगठनों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) के माध्यम से चलाई जा रही है।

(घ) सार्थक आजीविका कार्यकलापों और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले किंतु अब ठीक हो चुके लोगों को कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आजीविका में

सहायता देने वाले कार्यक्रम नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के पीडित हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) और जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी) सहित सहायता अनुदान संस्थान (जीआईए) के माध्यम से चलाए जाते हैं। यह विभाग कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग और अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य एजेंसियों/संस्थानों एवं नशा मुक्त भारत अभियान से जुडे आध्यात्मिक संगठनों के सामंजस्य से ऊपर उल्लिखित गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

(ड) नशीले पदार्थों की मांग कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य-योजना को पुनर्व्यस्थित करने के लिए विभाग द्वारा अनेक हितधारकों- राज्य सरकारों/ संघ राज्य-क्षेत्रों, एनजीओ/ सीबीओ और जीआई, विशेषज्ञों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कारागार आदि सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ चिंतन शिविरों और क्षेत्रीय समीक्षा/परामर्श कार्यक्रमों सहित परामर्श कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। निरंतर प्रयास करने के लिए, एनएपीडीडीआर के दिशानिर्देशों को पुनर्व्यस्थित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है।

डॉ. नरेश बंसल ने पहली सप्लीमेंट्री ने पुछा कि मा० सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से जानना चाहता हूं कि, भारत में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की लत से निपटने के लिए क्या कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन उपलब्ध है, अब तक इस हेल्पलाइन पर कितने कॉल प्राप्त हुए और क्या इस तंत्र को प्रभावी और सफल माना जा रहा है।

जिसके उत्तर मे माननीय श्री बी.एल.वर्मा जी (सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री) ने सदन मे बताया कि हमारे मंत्रालय ने 24 घण्टे एक राष्ट्रीय टोल फ्री न० 14446 का संचालन हो रहा है इस टोल फ्री का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों का दुरूपयोग करने वालों को टेली परामर्श प्रदान करना उन्हें निकटतम नशा मुक्ति केंद्र के लिए रेफर करना भी है और टोल फ्री पर कार्य परामर्शदाता, शिक्षित परामर्शदाता बैठे हुए हैं। इस पर अब तक 4 लाख 30 हजार से भी ज्यादा कॉल प्राप्त हुए हैं और सफलतापूर्वक यह हेल्पलाइन कार्य कर रही है।

डॉ. नरेश बंसल ने संबंधित प्रशन कि दुसरी सप्लीमेंट्री मे पुछा कि मा० सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से जानना चाहता हूं कि, क्या नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत किसी आध्यात्मिक या धार्मिक संस्था के सहयोग के लिए सम्पर्क किया गया है यदि हां तो इस सहयोग से अब तक कितने व्यक्तियों तक प्रभावी पहुंच या परिवर्तन सुनिश्चित हुआ है।

जिसके उत्तर मे माननीय श्री बी.एल. वर्मा (सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री) ने सदन मे बताया कि अगस्त, 2020 से नशा मुक्ति भारत अभियान प्रारंभ हुआ और लगातार सभी के सहयोग से इसमें कार्य किया जा रहा है। ब्रह्मकुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग, संत निरंकारी मिशन, गायत्री परिवार, इस्कॉन, श्रीरामचंद्र मिशन से हमारा एमओयू हुआ है और लगातार हम और भी आध्यात्मिक संस्थाओं से सम्पर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है निकट वर्ष में और भी संस्थायें जुडेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पर आगे बढेंगे। और इनके माध्यम से अब तक हम 3 करोड 37 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को नशे के विरूद्ध जागरूक करने का कार्य किया गया है।

यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 131वीं बैठक संपन्न

यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 131वीं बैठक में सरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ परियोजना के प्रस्तावों सहित कई अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

इस संबंध में जानकारी देते हुए यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल ने बताया कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन को गति देने के लिए बैठक में प्रस्तावित 120 मेगावाट क्षमता की सरकारी भ्योल रुपसियाबगड़, 102 मेगावाट की मोरी त्यूणी तथा 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी क्रम में सरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ परियोजना के विद्युत यांत्रिक कार्यों की पुनरीक्षित लागत भी शामिल है। डॉ. संदीप सिंघल ने बताया कि उक्त परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में काफी सुधार होगा और राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने में सहयोग प्राप्त होगा।

डॉ. सिंघल ने आगे बताया कि निदेशक मंडल ने निगम के परिचालन के अंतर्गत विद्युतगृहों एवं अन्य घटकों को वर्ष 2026-27 हेतु बीमित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ 1907 में स्थापित 3.5 मेगावाट की गलोगी लघु जल विद्युत परियोजना के आर.एम.यू. के पश्चात कैपिटल संशोधित टैरिफ के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। डॉ. संदीप सिंघल ने बताया कि ग्यारह वृहद जल विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ पिटिशन के विचलन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का भी संज्ञान निदेशक मंडल द्वारा बैठक में लिया गया।

बैठक में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एवं अध्यक्ष यूजीवीएन लिमिटेड आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मिनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव वित्त हिमांशु खुराना के साथ ही इंदु कुमार पांडेय, बी.पी. पांडेय, पराग गुप्ता, प्रबंध निदेशक यूजेवीएन लिमिटेड डॉ. संदीप सिंघल, प्रबंध निदेशक पिटकुल पी.सी. ध्यानी, निदेशक परियोजनाएं सुरेश चन्द्र बलूनी, निदेशक परिचालन ए.के.सिंह, अधिशासी निदेशक वित्त सुधाकर बडोनी आदि उपस्थित रहे।

आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन एवं करदाता सेवाएं विषय पर कार्यक्रम आयोजित

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एवं उत्तराखंड की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, श्रीमती अपर्णा करण ने करदाताओं को समुचित आयकर देने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।

आयकर विभाग देहरादून के तत्वाधान में "आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन एवं करदाता सेवाएं" विषय पर आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन के सभागार में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजन का शुभारम्भ आयकर विभाग के उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एवं उत्तराखंड प्रभार की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, श्रीमती अपर्णा करण ने दीप प्रजवाल्लित से किया। समारोह में श्रीमती रेणुका जैन गुप्ता, मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून, श्रीमती सुनीता सिंह, प्रधान आयकर आयुक्त, देहरादून, श्री शेओदान सिंह भदौरिया, प्रधान आयकर आयुक्त, (ओ.एस.डी.), कानपुर, श्री योगीश नायक, सी.सी.एफ. (ओएनजीसी) एवं श्री के. आर. बाबू, सी.ओ.आई.-आई.डी.-डब्लू. ई०. (ओएनजीसी) भी शामिल रहे।

मुख्य अतिथि श्रीमती अपर्णा करण, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एवं उत्तराखंड प्रभार द्वारा क्षेत्र के शीर्षस्थ करदाता के रूप में ओएनजीसी (कॉर्पोरेट श्रेणी) एवं रिषभ पन्त (व्यक्तिगत श्रेणी) को कार्यक्रम में सम्मानित किया। श्रीमती अपर्णा करण, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर द्वारा अपने उद्बोधन में क्षेत्र के करदाताओं को समुचित आयकर देने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उनकी समस्याओं का विभाग द्वारा शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। इसके अलावा श्रीमती अपर्णा करण ने टीडीएस एवं एडवांस टैक्स में कमी पर आयकर दाताओं को आगाह किया और समय से कर चुकाने की अपील की। कार्यक्रम में श्री अमरपाल सिंह, अपर आयकर आयुक्त, (टी.डी.एस.), देहरादून ने टी.डी.एस प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न अनुपालनों के सम्बन्ध में जानकारी साझा की। कार्यक्रम में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बार एसोसिएशन, शहर के विभिन्न व्यापर मंडलों के पदाधिकारियों एवं सदस्य उपस्थित रहे। श्री विपिन नागलिया, श्री सुनील मैसन नें व्यापर संघ देहरादून एवं श्री सिद्धार्थ अग्रवाल नें उत्तराखंड बिल्डर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधितव किया। इसके अतिरिक्त श्री परिमल पटेट, श्री रवि महेश्वरी एवं श्री राजीव साहनी, सीए एसोसिएशन, देहरादून तथा श्री तुषार सिंघल, टैक्स बार एसोसिएशन देहरादून की ओर से उपस्थित रहे। श्री एस. के. चटर्जी, आयकर आयुक्त (अपील) ने कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।

चमोली प्रकरण पर बाल आयोग की कठोर प्रतिक्रिया

चमोली जनपद में एक शिक्षक द्वारा एक बालिका के साथ कथित अश्लील व्यवहार किए जाने की गंभीर घटना पर आयोग ने गहरी चिंता व्यक्त की है। डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि यह घटना बच्चों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है तथा ऐसी अमानवीय घटनाओं को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आयोग ने निर्देशित किया है कि 'चमोली प्रकरण में पुलिस द्वारा की गई अब तक की समस्त कार्रवाई की विस्तृत आख्या (ATR) आयोग को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। राज्य के सभी स्कूलों, आश्रमों, छात्रावासों एवं बाल देखभाल संस्थानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराया जाए। वर्तमान तथा भविष्य में नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों की नियुक्ति मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Psychological Evaluation) के उपरांत ही सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों के लिए पूर्णतः सुरक्षित वातावरण स्थापित हो सके।'

साथ ही, जिलाधिकारी एवं SSP चमोली को निर्देश दिए गए हैं कि 'उक्त प्रकरण में तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। घटना से संबंधित पूरी कार्यवाही की त्वरित आख्या आयोग को भेजी जाए।'

'बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता'

डॉ. खन्ना ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग इस प्रकार के मामलों में शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाता है और किसी भी लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।

राज्यपाल ने किया एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ

एम्स ऋषिकेश में आज हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने किया। फ्रेंच एकेडमी ऑफ मेडिसिन तथा एयरबस फाउंडेशन के सहयोग से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज से शुरुआत हुई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियनों और पायलटों को उच्च स्तरीय आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल ने इसे उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए "जीवनरक्षक पहल" और "एक नई आशा" बताया।

राज्यपाल ने कहा कि किसी भी आपदा या दुर्घटना के पश्चात् 'गोल्डन आवर' में चिकित्सा सहायता मिलना जीवन बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क मार्ग बाधित होने, भूस्खलन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उपचार में कठिनाई रहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस उत्तराखण्ड के लिए एक वरदान सिद्ध होगी।

राज्यपाल ने कहा कि हेलीकॉप्टर में उपचार देना अत्यधिक जटिल कार्य है, जिसके लिए विशेष दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। यह प्रशिक्षित दल भविष्य में अनगिनत जिंदगियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने फ्रेंच एकेडमी ऑफ मेडिसिन तथा एयरबस फाउंडेशन द्वारा भारत के साथ किए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह ज्ञान-साझेदारी भारत के स्वास्थ्य तंत्र को और मजबूत बनाएगी तथा डॉक्टरों और छात्रों को वैश्विक मानकों का अनुभव प्रदान करेगी।

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए एआई आधारित निदान, ड्रोन के माध्यम से दवाओं का परिवहन, टेलीमेडिसिन तथा हेली एंबुलेंस जैसी नवाचार-आधारित सेवाएं भविष्य में स्वास्थ्य तंत्र को और मजबूत करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सेवा न केवल उत्तराखण्ड बल्कि पूरे देश के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। उन्होंने एम्स ऋषिकेश द्वारा 'प्रोजेक्ट संजीवनी' के अंतर्गत नि:शुल्क हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू करने को "मानवता की सच्ची सेवा" कहा। उन्होंने केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा उत्तराखण्ड सरकार के समन्वित सहयोग की सराहना की।

इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश की निदेशक डॉ. मीनू सिंह, डीन अकादमिक प्रो. जया चतुर्वेदी, फ्रेंच एकेडमी ऑफ मेडिसिन के महासचिव रिचर्ड विलेट, डॉ. कमर आजम, डॉ. मधुर उनियाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

डॉ. गीता खन्ना, अध्यक्ष-उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा समर्पण खुला बाल आश्रय, चंद्रनगर में ओएनजीसी सीएसआर के सहयोग से प्रदान की गई 'वाहन एवं स्मार्ट बोर्ड' का उदघाटन किया गया।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

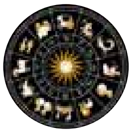
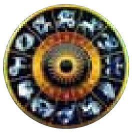
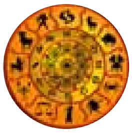

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि– कुछ समय आत्मचिंतन तथा आत्म मनन में जरूर व्यतीत करें। पब्लिक डीलिंग संबंधी कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अनजान लोगों पर ज्यादा भरोसा न करना ही बेहतर है। व्यावसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। परिजनों के बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य उचित बना रहेगा। भाग्यशाली रंग– लाल, भाग्यशाली अंक– 1

वृषभ राशि– मित्रों तथा संबंधियों के साथ मुलाकात के अवसर बनेंगे। व्यावसायिक महिलाएं अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम हासिल करेंगी। किसी अपरिचित व्यक्ति से व्यावसायिक गतिविधियों को साझा न करें। प्रेम साथी के साथ घूमने का मौका मिलेगा। पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। भाग्यशाली रंग– हरा, भाग्यशाली अंक– 6

मिथुन राशि– लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। समय खुशनुमा और मनोरंजक व्यतीत होगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दांपत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहेगा। धैर्य और संयम से काम लें। मीडिया से संबंधित गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, कोई खास फायदेमंद सूचना मिल सकती है। भाग्यशाली रंग– आसमानी, भाग्यशाली अंक– 5

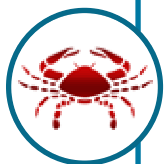

कर्क राशि– आपके कार्य व्यवस्थित तरीके से संपन्न होते जाएंगे। आध्यात्मिकता की ओर भी रुझान बढ़ेगा। बड़े बुजुर्गो के सहयोग से घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। पुराने मामलों से आपसी संबंधों में तनाव रहेगा। व्यावसायिक कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की उम्मीद है। भाग्यशाली रंग– नीला, भाग्यशाली अंक– 7

सिंह राशि– समय बहुत ही बेहतरीन है। लाभदायक अनुबंध मिल सकते हैं। व्स्वभाव में लचीलापन लाएं, आपकी किसी जिद की वजह से पारिवारिक समस्या बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यप्रणाली में बदलाव संबंधी जो योजनाएं हैं, वह फायदेमंद साबित होंगी। घर का माहौल भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। भाग्यशाली रंग– सफेद, भाग्यशाली अंक– 1

कन्या राशि– अपनी प्रतिभा को जाहिर करने का सही समय है। किसी मित्र की सलाह से आप कोई महत्वपूर् ण निर्णय लेने में भी सक्षम रहेंगे। पारिवारिक गतिविधियों की वजह से व्यस्तता पूर्ण दिन व्यतीत होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता भी मिलेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्यशाली रंग– बादामी, भाग्यशाली अंक– 2

तुला राशि– घर के वरिष्ठ लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से घर में शांति पूर्ण माहौल रहेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात खुशनुमा रहेगी। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज्यादा रोक टोक करने से उनका मनोबल कमजोर पड़ेगा। सुकून पाने के लिए अध्यात्म का सहारा लें। विवाहित जीवन सामंजस्य पूर्ण रहेगा। भाग्यशाली रंग– केसरिया, भाग्यशाली अंक– 9

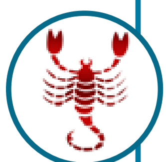

वृश्चिक राशि– पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल भरी दिनचर्या से आज कुछ राहत मिलेगी। युवा वर्ग को इंटरव्यू आदि में उचित सफलता मिलने की संभावना है। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। दूसरों की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी होने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भाग्यशाली रंग– लाल, भाग्यशाली अंक– 1

धनु राशि– आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा। कोई मनोरंजन यात्रा का भी कार्यक्रम बनेगा। विदेश जाने के लिए इच्छुक लोग अपना कागजी कार्यवाही सावधानी से करें। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा तथा सभी सदस्यों के बीच प्रेम पूर्ण व्यवहार रहेगा। भाग्यशाली रंग– गुलाबी, भाग्यशाली अंक– 2

मकर राशि– पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बनेंगी। सामाजिक गतिविधियों में सहयोग दें। निवेश करने से भी परहेज करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ वार्तालाप और मनोरंजन में सुखद समय व्यतीत होगा तथा आपसी संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। वर्तमान मौसम और प्रदूषण से अपना बचाव रखें। भाग्यशाली रंग– बादामी, भाग्यशाली अंक– 3

कुंभ राशि– ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, कि सामाजिक स्तर पर आपको एक नई पहचान हासिल होने वाली है। प्रभावशाली संपर्क बनेंगे। घर में शांति पूर्ण माहौल रहेगा। विद्यार्थी भी इस समय अपनी पढ़ाई में ध्यान न देकर अपना नुकसान ही करेंगे। कोई आधिकारिक यात्रा संभव है। घर में शांति पूर्ण माहौल रहेगा। भाग्यशाली रंग– नारंगी, भाग्यशाली अंक– 6

मीन राशि– व्यवस्थित दिन व्यतीत होगा। युवा वर्ग अपनी उच्च शिक्षा और करियर को लेकर सजग रहेंगे। संपत्ति में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक समस्या से बचने के लिए अपना बजट सुनिश्चित करें और खर्चों पर काबू रखें। व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से कोई खास फायदेमंद सूचना मिल सकती भाग्यशाली रंग– आसमानी, भाग्यशाली अंक– 4

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

Pahad ki Mahilaon Dwara Banaya Gaya

Pure & Natural

A2 Badri Cow Ghee

A2 Beta Protein

Bilona Method

Immunity Booster

fssai 22623030001586

UDYOG AADHAR MSME UK050061483

THE DOON HIMALAYAN AGRO FOODS
Dalanwala, Dehradun
Customer Care - 7409782771

Available at

KUMAR SWEETS
Sahastradhara Road,
Near Crossing, Dehradun
7017180869

PLANET JR
Panditwadi,
Chakrata Road, Dehradun
9897477151